

समावेशी शिक्षा : प्रावधान, चुनौतियां और समाधान

डॉ सीताराम आठिया

साहित्यकार, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, समाजसेवी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी जिला सागर, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है, जिसमें शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, ताकि वे भी समाज का एक हिस्सा बन सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को बाल केंद्रित विधियों द्वारा विकसित किया जाना है और विद्यालय, घर व समाज में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों को विद्यालयीन शिक्षा में पहुँच की इस तरह आवश्यकता है, कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में संदर्भित करके समझा जाय। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, और उसे कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों की योग्यताएँ भी अलग अलग हो सकती हैं। अतः प्रत्येक कक्षा में विभिन्नताओं का होना भी स्वाभाविक है। भारत में कई विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ एक ही शिक्षक विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशिष्ट सामग्री, विधि, विषय वस्तु प्रदान कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत भी यही है कि एक सामान्य शिक्षक अपनी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बने। उसका उत्तरदायित्व न सिर्फ कक्षा के भीतर हो बल्कि बाहर भी अनंत तक हो। समावेशी शिक्षा इस बात को भी लागू करती है कि सामान्य विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता पूरी हो। कक्षा में प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करना ही समावेशी शिक्षा है। जिस प्रकार हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार समावेशी दर्शन में सभी छात्रों को एक समान माना जाता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएँ

समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले जैसे मन्दबुद्धि, अन्धे, बहरे, प्रतिभा शाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जाँच की जाती है, उसके तुरन्त बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। मानव

संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले चाहे वो बालक हो या युवा, अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय पूर्व व्यवस्था विद्यालय एवं सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हो। समावेशन का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुख्यधारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा प्राप्त करना है, जो शायद असम्भव नहीं है। सच तो यह है कि जब हम विभिन्नताओं को सहेजते हुए उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि क्रियान्वयन की प्रणाली भी जटिल एवं कठोर होगी तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। यूनेस्को ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जेनेवा 25-28, 2008 में समावेशी शिक्षा पर दस प्रश्न अति संवेदनशील एवं सीमान्त समूह सम्बन्धी वार्ता में स्पष्ट किया है कि “समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समृद्ध बनाती है। अति संवेदनशील एवं सीमान्त समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। स्टीफन तथा ब्लेकहर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित (पूर्ण रूप से अपंग नहीं) बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है।

शिक्षा और प्रशिक्षण में विशेष आवश्यकताओं के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसएनईटी) के अनुसार, समावेशी शिक्षा को एक सीखने के माहौल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जाति, वर्ग, लिंग, विकलांगता, धर्म, यौन प्राथमिकता के भेदभाव के बिना सभी शिक्षार्थियों के पूर्ण व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है।

सेंटर फॉर स्टडीज़ इन इनक्लूसिव एजुकेशन (CSIE) के अनुसार, सीखना तभी पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है, जब वह समावेशी हो।

समावेशी शिक्षा क्या है?

शिक्षा प्रणाली में भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम बनाया। शैक्षणिक संस्थान भेदभावपूर्ण आधार पर किसी बच्चे के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते या बच्चों पर लेबल नहीं लगा सकते। इसी अधिनियम ने समावेशी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक सरल अवधारणा है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को, उसकी पृष्ठभूमि, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं, लिंग आदि के भेदभाव के बिना, समान उपचार और सीखने

के अवसर मिलें। यह दृष्टिकोण इस विश्वास से लिया गया था कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में छात्र अपने व्यक्तित्व निर्माण, भावनात्मक सुदृढता, अपनी और अपने साथियों की ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना और टीम वर्क को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना शुरू कर देता है। यह सब दिव्यांगों के जीवन में बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे उन्हें उनकी वृद्धि और विकास में आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

समावेशी शिक्षा की रणनीतियाँ

एक शैक्षिक दृष्टिकोण के रूप में, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। एक समावेशी कक्षा में, शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू करते हैं कि सभी छात्र सार्थक शिक्षण अनुभवों तक पहुंच सकें और उनमें भाग ले सकें। समावेशी शिक्षा के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ अनुसरण की जाती हैं:

1. विभेदित निर्देश

इसमें समावेशी कक्षा में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों, सामग्रियों और मूल्यांकन को अपनाना शामिल है। कुछ तकनीकों में बदलती सामग्री प्रस्तुति, छात्रों को सामग्री से जुड़ने के लिए कई तरीके प्रदान करना, विभिन्न मूल्यांकन विधियों की पेशकश आदि शामिल हो सकते हैं।

2. सहयोगात्मक शिक्षण

इस दृष्टिकोण में सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा और शिक्षक समावेशी कक्षा में निर्देश की योजना बनाने, वितरित करने और मूल्यांकन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, सहयोगात्मक शिक्षण इस तरह दिख सकता है।

सह-शिक्षण: - शिक्षक निर्देश और छात्र सहायता के लिए जिम्मेदारियाँ साझा करते हैं। परामर्श:- शिक्षक निर्देश की योजना बनाने और उसका मूल्यांकन करने में सहयोग करते हैं, जिसमें एक शिक्षक वितरण में अग्रणी होता है।

सहायक शिक्षण:- एक शिक्षक विशिष्ट छात्रों को लक्षित सहायता प्रदान करता है जबकि दूसरा निर्देश का नेतृत्व करता है।

3. लचीला समूहन

छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों या जरूरतों के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, जिससे लक्षित निर्देश और समर्थन की अनुमति मिलती है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

• सजातीय समूहन: समान आवश्यकताओं या क्षमताओं वाले छात्र एक साथ काम करते हैं।

• विषम समूहन: विविध आवश्यकताओं या क्षमताओं वाले

छात्र एक साथ काम करते हैं।

• रुचि-आधारित समूह: साझा रुचि वाले छात्र किसी परियोजना या गतिविधि पर एक साथ काम करते हैं।

समावेशी शिक्षा के लाभ

समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षाशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है। शैक्षिक समावेशन कई लाभ प्रदान करता है, जो सीखने के अनुभव को बेहतर बनाता है और आवश्यक जीवन कौशल विकसित करता है। विद्यालयों में समावेशित शिक्षा सम्मिलित करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

1. सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देना :

समावेशी शिक्षा छात्रों को विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों से अवगत कराकर सहानुभूति और करुणा सीखने में मदद करती है। यह छात्रों को मतभेदों की बेहतर समझ और सराहना विकसित करने में भी सक्षम बनाता है। सहानुभूति और करुणा उच्च भावनात्मक भागफल के मजबूत संकेतक हैं, जो आज के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. समान अवसर प्रदान करना :

समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या विकलांगताओं के बावजूद उन्हें सीखने के समान अवसर प्राप्त हो। जब प्रत्येक छात्र को समान व्यवहार और अवसर मिलते हैं, तो यह एक बेहतर समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। जो माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे एक समृद्ध और सामंजस्य पूर्ण समाज में रहें, उन्हें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए।

3. अपनेपन की भावना स्थापित करना

समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह बच्चों में अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद करती है और सभी छात्रों को मूल्यवान और सम्मानित महसूस कराती है। एक समान कक्षा का माहौल बनाती है, जिससे प्रत्येक बच्चा आगे बढ़ सकता है और सफल हो सकता है।

4. विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना :

दुनिया भर के अग्रणी शिक्षक, छात्रों के बीच विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समावेशी शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। आज के बहुसांस्कृतिक समाज में यह समय की मांग है। जो बच्चे स्वीकार्यता और समझ की संस्कृति में बड़े होते हैं, उनके लिए विविधतापूर्ण समाज में घुलना-मिलना आसान

होता है। यह एक विशेषता छात्रों को भविष्य में विदेशी अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतर बना सकती है।

5. समस्या-समाधान कौशल विकसित करना :

समावेशी शिक्षा छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और विभिन्न शिक्षण शैलियों को शीघ्रता से अपनाने की चुनौती देती है। समय के साथ यह उनमें समस्या-समाधान कौशल विकसित और पोषित करता है, जो आज की जटिल जीवन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक है।

6. बेहतर संचार और सामाजिक कौशल

समावेशी शिक्षा में विविध क्षमताओं और पृष्ठभूमि वाले छात्र, मजबूत संचार और सामाजिक कौशल विकसित करते हुए बातचीत और सहयोग करते हैं। ये कौशल छात्रों को विभिन्न सामाजिक स्थितियों से निपटने और कक्षा के अंदर और बाहर अपने साथियों के साथ स्थायी संबंध बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण हैं।

7 उन्नत शैक्षणिक प्रदर्शन

समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों को अपने साथियों के समान पाठ्यक्रम तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिससे अक्सर उच्च शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उचित आवास और सहायता के साथ, विकलांग छात्र सक्रिय रूप से सीखने में संलग्न हो सकते हैं, विषय वस्तु की अपनी समझ बढ़ा सकते हैं और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

हम देखते हैं कि मात्रात्मक शिक्षा की अपेक्षा गुणात्मक शिक्षा अधिक लाभदायक होती है। इसीलिए शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु समावेशी शिक्षा आवश्यक है। यदि सभी शिक्षार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं:

1. कौशल का विकास: समावेशी शिक्षा सहयोगी कौशल, सहन - शीलता जैसे विभिन्न कौशल विकसित करने में मदद करती है तथा समावेशी वातावरण में छात्र एक-दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं।
2. आत्मविश्वास का विकास: समावेशी शिक्षा विकलांग विद्यार्थियों के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण प्रदान करती है, जिससे वे आसानी से अपने विचार अन्य बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं और सामान्य बच्चों की तरह गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। परिणाम स्वरूप, समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों में आत्मविश्वास के विकास में सहायता करती है।
3. सभी विद्यालयों में सब के लिए शिक्षा : - समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा बाधित बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं।

4. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बालकों की स्वीकृति तथा समर्थन :- समावेशी शिक्षा पद्धति में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बालकों जैसे- शारीरिक, श्रवण, दृष्टि एवं वाणी रूप से बाधित, मानसिक असमर्थता आदि सभी बालकों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकार करती है, उन्हें समर्थन तथा उनके अच्छे विकास के अवसर प्रदान करती हैं।
5. सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध : समावेशी शिक्षा पद्धति में सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय तथा समाज में निकटतम संबंध होने से सभी बालकों को अधिकतम लाभ मिलता है।
6. विद्यालय की जिम्मेदारी: - समावेशी शिक्षा पद्धति इस बात को स्पष्ट मान्यता देती है कि सभी बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए समुचित प्रावधान का आयोजन करना संस्थान की जिम्मेदारी है।
7. समाज का विकास: समावेशी शिक्षा से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है। अच्छी शिक्षा प्रणाली से छात्रों का विकास बेहतर तरीके से होता है और वे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
8. राष्ट्र का विकास: गरीबी और भेदभाव के कारण किसी देश का विकास बहुत कठिन है। समावेशी शिक्षा द्वारा इन सभी कारकों को समाप्त किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र की प्रगति अच्छे तरीके से हो सकती है।
9. आत्म अवधारणा का विकास: समावेशी शिक्षा छात्रों में आत्म अवधारणा विकसित करने में सहयोग करती है। जिससे शिक्षार्थी स्वयं को आसानी से समझ सकते हैं। वे अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जान सकते हैं।
10. शिक्षा का सार्वभौमीकरण: शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु समावेशी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अनुसार : समावेशन के बिना शिक्षा का सार्वभौमीकरण हासिल नहीं किया जा सकता।
11. सामाजिक समानता की प्राप्ति हेतु : समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। एक समावेशी वातावरण में सभी शिक्षार्थी चाहे वह विकलांग हों या सामान्य, समान अवसरों और जिम्मेदारियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज में समानता प्राप्त करने में सहायता करती है।

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य:

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. सबके लिए शिक्षा
2. कौशल की पहचान
3. व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करें.

4. सामाजिक चेतना की पहचान.
5. स्वाभिमान की भावना का विकास करना
6. सामाजिक समानता
7. अपने पर भरोसा रखनेवाला
8. यह सुनिश्चित करना कि सभी विविध शिक्षार्थियों को उनकी अलग-अलग रुचि और क्षमताओं के अनुसार संसाधन मिले।
9. सभी छात्रों के पास शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धि के अधिक अवसर हो।
10. दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करना क्योंकि वे ही देश के भावी नागरिक हैं।

समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ और उनका समाधान

समावेशी शिक्षा एक उत्कृष्ट शिक्षा पद्धति है जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति मिलना चाहिए, किंतु इसके सुचारू क्रियान्वयन में निम्नलिखित अवरोध हैं:

1. सोच तथा दृष्टिकोण

दिव्यांगता के प्रति आम आदमियों की सोच तथा देखने का नजरिया समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी कार्य की अक्षमता या दिव्यांगता किसी भी बच्चे या मनुष्य में होना एक सामान्य बात है। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में किसी कार्य को सम्पादित करने में अक्षम हो सकता है। जैसे चोट लगने पर हाथ पैरों में प्लास्टर बंधने से मनुष्य को कई कार्य दूसरो की सहायता से करने पडते हैं। तथा वृद्धावस्था में शारीरिक अंगों के शिथिल होने जैसे आंख से कम दिखाई देना अथवा श्रवण क्षमता क्षीण हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी न कभी दिव्यांग हो जाता है अर्थात् अक्षमता प्रत्येक मानव जीवन की अनचाही किन्तु अपरिहार्य तथा प्राकृतिक घटना है। इस अटल सत्य को जानने के बाद भी लोग दिव्यांग तथा अक्षम व्यक्तियों के प्रति एकाग्र दृष्टिकोण तथा उनके प्रति भेदभाव रखते हैं। आज भी अनेक समाजों में यह धारणा है कि, दिव्यांगता पूर्वजन्मों के अनुचित कर्मों का प्रतिफल है। अतः ऐसे व्यक्ति या बच्चो का सहयोग करने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना।

अतः लोगो को ऐसी सोच को बदलने के लिए सरकार को चाहिए कि वह दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित जन जाग्रति शिविर लगाए। लोक कल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगों को लाभान्वित करे ताकि उनकी हीन भावना दूर हो सके। गैर सरकारी संगठनों को भी इस दिशा में आगे आकर दिव्यांगता के संबंध में समाज में जन जाग्रति लाना चाहिए।

2. दोषपूर्ण आधारभूत ढाँचा

दिव्यांग बच्चों के अध्ययन हेतु बनाए गए विद्यालय भवनों की बनावट तथा उनके आधारभूत ढाँचे के निर्माण में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कोई सुधार नहीं किया जाता है जिससे दिव्यांग बच्चो की मूलभूत

आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः ऐसे विद्यालयों के निर्माण में इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमें दिव्यांग छात्रों की सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो।

3. संदर्भ शिक्षकों तथा विशेषज्ञों का अभाव

मात्र दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश कराने से शैक्षिक समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में सभी अक्षमताओं के प्रथक पृथक संदर्भ शिक्षक नियुक्त करना सम्भव नहीं होता है किंतु संकुल स्तर पर या प्रत्येक विकासखण्ड में प्रत्येक अक्षमता से संबंधित एक विशेष शिक्षक या संदर्भ शिक्षक की नियुक्ति अवश्य की जा सकती है। इन संदर्भ शिक्षकों की सेवाएँ समस्त विद्यालयों में जहाँ ये दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं, उनमें आवश्यकतानुसार ली जा सकती है।

पूर्व में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक-एक संदर्भ शिक्षक की नियुक्ति की गयी थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी संदर्भ शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। संदर्भ शिक्षकों की सहायता से दिव्यांग बच्चों के शिक्षण तथा दैनिक जीवन कौशल के विकास में सहायता मिलती है। वित्तीय बाध्यताये भी समावेशी शिक्षा की राह का मुख्य अवरोध है, जिसके कारण विशेषज्ञों तथा संदर्भ शिक्षकों की सुविधाएँ नहीं लेना दिव्यांग बच्चों के समावेशन को और चुनौतपूर्ण बना देता है। अतः शासन को समावेशी शिक्षा के विकास हेतु पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

4 संसाधनों की कमी

शैक्षिक समावेशन की दिशा में यथोचित संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या है। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की प्रकृति के अनुसार आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। अक्षमता के अनुरूप आवश्यक उपकरण बच्चों को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस दिशा में अच्छे प्रयास किये हैं। इसके अतिरिक्त अधिगम में आवश्यक सहायता सामग्री का भी अभाव होता है, पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल, स्लेट, एवाकस, टेलीफ्रैम जैसे आधारभूत शैक्षिक उपकरण जो कि बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं हैं, विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। इसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैग्निफायर, लार्ज प्रिंट, पुस्तकें आवश्यक हैं। इनके अभाव में दृष्टिबाधित बच्चों का शिक्षण नहीं हो पाता है। श्रवण बाधित बच्चों को भी जरूरत के मुताबिक श्रवण यंत्र प्राप्त नहीं होते हैं। अतः सरकार को इन संसाधनों, उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

5. जागरूकता, परामर्श तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की कमी

उचित शिक्षा तथा परामर्श की अप्राप्ति के कारण जनसाधारण तथा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता तथा अभिभावकों में दिव्यांगता के प्रति नकारात्मकता का भाव होता है। ऐसे अभिभावक प्रायः अपने दिव्यांग बच्चों के प्रति अनावश्यक रूप से चिन्तित रहते हैं या आशंकित रहते हैं या उनकी ओर बिल्कुल

भी ध्यान नहीं देकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। जबकि अनेकों राज्य सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएँ, भारतीय पुर्नवास परिषद तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। निःशुल्क विशेषज्ञ परामर्श शिविर आयोजन किये जाते हैं। सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर तथा उनमें आवश्यक संशोधन करके दिव्यांगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन जागरूकता तथा जानकारी के अभाव में वे इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। विभिन्न शोध तथा सर्वेक्षणों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि जागरूक तथा जानकार अभिभावक दिव्यांगता के प्रति स्पष्ट, वैज्ञानिक तथा सही सोच रखते हैं। वे विद्यालयों में भी शिक्षकों के सम्पर्क में रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। अतः शैक्षिक समावेशन के लिए आवश्यक है कि दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में व्यापक जन शिक्षा तथा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।

6. गरीबी

भारत में अधिकांश दिव्यांग बच्चे अधिकांश अत्यधिक गरीब परिवारों से आते हैं। गरीबी के कारण दिव्यांगता की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है। कुपोषण तथा सुविधाओं के अभाव में गर्भवती महिलाएँ कई बार शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं। गरीबों को समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, उचित चिकित्सा तथा परिवहन सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती जिससे दिव्यांगता बढ़ने की संभावना अधिक होती है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चों के एस्कार्ट तथा परिवहन के लिए अलग से धनराशि आवंटित की गयी जो अपर्याप्त थी और इससे सभी दिव्यांग लाभान्वित भी नहीं हो पाए थे। अतः सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देकर चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परिवहन की निशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहिए।

7 शिक्षकों की व्यवहारिक प्रशिक्षण का अभाव

शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे डी०एल०एड, विशेष डीएलएड, बी० एड०, एम०एड० में समावेशी शिक्षा से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं है। और जो है वो मात्र सैद्धान्तिक पक्ष तक ही सीमित है। शिक्षकों को अक्षमता संबंधी व्यावहारिक ज्ञान नहीं होने से कक्षा में अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों के शिक्षण में उन्हें कठिनाई होती है। जिससे शिक्षक धीरे- धीरे इन दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और शैक्षिक समावेशन का उनका किताबी अध्ययन शिक्षण कक्षा में असफल हो जाता है।

दूसरी ओर सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी यही स्थिति है। क्योंकि पहले तो उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित ही नहीं किये जाते हैं, और जो प्रशिक्षण होते भी हैं तो उनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब होती है। समावेशी शिक्षा में सुधार हेतु सेवारत शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे

दिव्यांग बच्चों की गतिविधियों तथा उनकी समस्याओं के व्यवहारिक पक्ष को समझ सकें तथा सैद्धान्तिक ज्ञान का धरातलीय अनुभव कर सकें।

समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक प्रशासकों तथा गैर-शैक्षणिक अभिकर्मियों के लिए भी संवेदीकरण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएँ आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। ताकि वह भी दिव्यांग बच्चों के दैनिक जीवन कौशल तथा आवश्यकताओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके।

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में स्कूलों की भूमिका

समावेशी शिक्षा का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब शिक्षक और अभिभावक मिलकर काम करें। चूँकि छात्र अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताते हैं, इसलिए शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए व्यापक अनुसंधान, योजना निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उत्कृष्ट स्कूल अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित कर समावेशी कक्षाएँ बनाने के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम को भी प्रत्येक छात्र की सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा सभी प्रकार के छात्रों को समायोजित हेतु स्कूल के बुनियादी ढांचे को बदलना भी आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के बारे में बुनियादी जानकारी, उसके प्रभावी कार्यान्वयन तकनीकों की खोज करना आदि कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय सुझाव हैं, जिन पर अमल करने से इस दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह देखा गया है कि जिन स्कूलों ने समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण को अपनाया और लागू किया है, वे अपने छात्रों को एक साथ बढ़ने, खेलने और सीखने के बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं।

आज, समानता की अवधारणा को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। चूँकि लोग प्रत्येक बच्चे को सीखने के समान अवसर देने के बारे में अधिक चिंतित हैं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा ने जोर पकड़ लिया है। चाहे आप विशेष सीखने की ज़रूरत वाले या बिना सीखने वाले बच्चों के गौरवान्वित माता-पिता हों, एक समावेशी स्कूल चुनना उनके समग्र विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

समावेशी शिक्षा की वर्तमान समय में प्रासंगिकता

समावेशी शिक्षा पर हुए शोधों से पता चला है कि इससे:

1. शिक्षा में समावेशन से विकलांगता और बिना विकलांग छात्रों को एक साथ सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। इससे बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि और समाजीकरण होता है और समुदाय एवम अपनेपन को भी बढ़ावा देता है, विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान को बढ़ावा देता है।
2. शिक्षा में समावेशन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सीखने और सफल होने के समान अवसर मिले। बेहतर

शैक्षणिक परिणाम, समर्थन और संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि, शिक्षक वृद्धि और विकास इसके महत्व को दर्शाते हैं।

3. सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम (बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन) की समृद्धि के संपर्क में आने पर अधिकांश छात्र बेहतर सीखते हैं और प्रदर्शन करते हैं।

4. समावेशन संबंध विकसित करने (बेहतर सामाजिक व्यवहार) के अवसर प्रदान करता है।

5. किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले लोगों के साथ सहजता का स्तर विकसित होता है और सक्षम लोगों द्वारा उनकी अधिक देखभाल करने से दिव्यांग बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें पूरी होती हैं।

6. विकलांग छात्रों के सहपाठी भी सामाजिक अनुभूति (एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज) में वृद्धि का अनुभव करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में समाज के विभिन्न वर्गों के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक योजनाओं के साथ विविधतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनता है कि हाशिए पर पड़े हुए, उन बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं। इनमें विकलांग सहित अन्य बाधाओं से पीड़ित बच्चों की संख्या अत्यधिक है। अतः वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा विकलांग एवं सामान्य दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जरूरत है तो बस ऐसे विशिष्ट छात्रों के संबंध में तथ्यपरक जानकारी एकत्रित की जाए, उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आकलन करते हुए उचित नीतियाँ बनायी जाए। जिससे शिक्षा से वंचित बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए नई दिशा दी जाए। गौरतलब है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों संबंधी स्थिति आज भी चिंताजनक है। आँकड़े बताते हैं कि विकलांग लोगों की आधी आबादी आज भी शिक्षा से दूर है। समाज के सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है कि वह समाज के इस वर्ग के अस्तित्व की महत्ता को उचित स्थान दें और उनके शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अपेक्षित कदम उठाये और उनके इस कार्य में समावेशी शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

संदर्भ सूची

समावेशी शिक्षा , बी एड स्पेशल पाठ्यक्रम, द्वितीय सेमेस्टर पुस्तक, उत्तराखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पेडर होज, आलेख, समावेशी शिक्षा को समझना: आदर्श और वास्तविकता

अंजलि सेठ, आलेख, छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा का महत्व

के आर मंगलम, गुड़गांव, समावेशी शिक्षा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?